आप के विधायक दल की बैठक में सर्वसम्मति से नेता चुनी गईं, केजरीवाल ने उपराज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंपा

आतिशी होंगी दिल्ली की नई सीएम

नई दिल्ली, प्रमुख संवाददाता। आप सरकार की मौजूदा शिक्षा एवं वित्त मंत्री आतिशी दिल्ली की अगली मुख्यमंत्री होंगी। आम आदमी पार्टी (आप) के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई विधायक दल की बैठक में आतिशी सर्वसम्मति से नेता चुनी गईं। आप के प्रदेश संयोजक गोपाल राय ने कहा कि दिलीप पांडेय की ओर से आतिशी के नाम का प्रस्ताव रखा गया था।

शाम 4.30 बजे उपराज्यपाल विनय सक्सेना से भेंट कर अरविंद केजरीवाल ने मुख्यमंत्री पद से अपना इस्तीफा सौंप दिया। इसके बाद आतिशी ने एलजी के समक्ष सरकार बनाने का दावा पेश किया। निर्वतमान मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आतिशी को नई पारी की शुभकामनाएं दी हैं।

इधर, आतिशी ने कहा कि मैं खुश हूं, लेकिन दुखी भी हूं, क्योंकि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफा दे दिया। मैं आप के सभी विधायकों और दिल्ली की दो करोड़ जनता की तरफ से कहना चाहती हूं कि दिल्ली का एक ही मुख्यमंत्री है और उसका नाम अरविंद केजरीवाल। भाजपा ने पिछले दो साल से केजरीवाल को परेशान करने और उनके खिलाफ षड्यंत्र रचने में कोई कसर नहीं छोड़ी। ऐसा आदमी जो आईआरएस की नौकरी ठुकरा सकता है, मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे सकता है, ऐसे ईमानदार आदमी पर भाजपा ने भ्रष्टाचार के आरोप लगाए, उन्हें झूठे केस में जेल में रखा। आतिशी ने पत्रकारों से कहा कि अब हमें अगले कुछ महीनों तक जमकर काम करना है। केजरीवाल ने जो विकास कार्य जनता के लिए शुरू किए हैं, उन्हें जारी रखना है। हमारा एक ही उद्देश्य है कि प्रचंड बहुमत के साथ केजरीवाल को दोबारा मुख्यमंत्री बनाया जाए।

›मन दुखी P02

एलजी से मिलकर सरकार बनाने का दावा पेश किया

नई दिल्ली स्थित राजभवन में मंगलवार को उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना को पत्र देकर सरकार बनाने का दावा पेश करतीं आतिशी। साथ में निर्वतमान मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल मौजूद थे • एजेंसी

14 विभागों का जिम्मा संभाल रहीं आतिशी ने केजरीवाल के जेल में रहने के दौरान राज्य की बागडोर संभाली

आतिशी ही क्यूं

- आतिशी पार्टी के साथ शुरुआती दिनों से जुड़ी हुई हैं। दिल्ली शिक्षा मॉडल समेत कई योजनाओं को आकार देने में अहम भूमिका रही।
- मनीष सिसोदिया व अरविंद केजरीवाल के जेल जाने के बाद सरकार में सबसे ज्यादा विभागों के साथ अपने काम को आगे बढ़ाया।
- पार्टी व सरकार के मुद्दों को हर मंच पर जोरदार तरीके से उठाती रहीं। अच्छी नीतिकार के साथ, सरकार में फिलहाल अच्छी पकड़ है।
- वह आम आदमी पार्टी के भरोसेमंद नेताओं में शामिल है।

“ चेहरा बदलने से आम आदमी पार्टी का चरित्र नहीं बदलेगा। केजरीवाल के नेतृत्व वाली पार्टी 10 वर्ष के शासन में भ्रष्टाचार के लिए अभी भी जवाबदेह है। नई मुख्यमंत्री को बताना होगा कि उन्होंने दिल्ली के लोगों को कैसे लूटा।

–**वीरेंद्र सचदेवा**, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष

“ आतिशी को शुभकामनाएं। उन्हें लोगों की समस्याएं हल करने व महिलाओं पर बढ़ते अत्याचार को रोकने लिए काम करना चाहिए। आप लोगों की समस्याओं को दरकिनार नहीं कर सकती है।

–**देवेन्द्र यादव**, दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष

पेजर धमाकों से दहला लेबनान, आठ की मौत

बेरूत, रायटरः लेबनान में मंगलवार को एक के बाद एक हुए हजारों पेजर धमाकों में आठ लोगों की मौत हो गई और ईरान के राजदूत मुज्तबा अमानी समेत 2750 लोग घायल हो गए। समझा जा रहा है कि हिजबुल्ला के लड़ाकों को निशाना बनाकर अत्याधुनिक तकनीक से धमाकों को अंजाम दिया गया। घायलों में बड़ी संख्या में डाक्टर भी हैं।

इस मामले में संपर्क किए जाने पर इजरायली सेना ने किसी तरह की टिप्पणी से इन्कार किया है। हालांकि हिजबुल्ला इसमें इजरायल का हाथ होने की बात की मान रहा है। वैसे यह अपने आप में पहला ऐसा मामला है, जिसने सुरक्षा एजेंसियों के होश उड़ा दिए हैं।

रायटर से बातचीत में हिजबुल्ला के एक अधिकारी ने बताया कि इजरायल के साथ लगभग एक वर्ष की लड़ाई में पेजरों के धमाके अब तक की सबसे बड़ी सुरक्षा चूक है। बीते वर्ष अक्टूबर में शुरू हुए गाजा संघर्ष के साथ ही ईरान समर्थित हिजबुल्ला, इजरायल के साथ सीमापार की लड़ाई लड़ रहा है।

सुरक्षा से जुड़े सूत्रों के अनुसार जिन पेजरों में धमाके हुए हैं, वो हिजबुल्ला द्वारा हाल ही के महीनों में खरीदे गए लेटेस्ट माडल के थे। शुरुआती धमाका स्थानीय समयानुसार शाम करीब पौने चार बजे हुआ, जिसके बाद इनमें विस्फोट का सिलसिला करीब एक घंटे तक जारी रहा। हालांकि अभी तक यह नहीं पता चल पाया है कि इन पेजरों में धमाके कैसे किए गए। लेबनान के आंतरिक सुरक्षा बल ने बताया कि विशेषरूप से बेरूत के दक्षिणी उपनगरों समेत देश में कई वायरलेस संचार उपकरणों में विस्फोट किया गया, जिससे लोगों को चोटें आईं।

इसके बाद घायलों को लेकर लोग स्थानीय अस्पतालों की तरफ भागे, जबकि एंबुलेंस और सुरक्षाबलों को भी

- निशाने पर थे हिजबुल्ला के लड़ाके, ईरान के राजदूत समेत 2,750 घायल
- हिजबुल्ला ने इजरायल के साथ लड़ाई में इसे सबसे बड़ी सुरक्षा चूक बताया

बेरूत में मंगलवार को पेजर धमाके के घायलों की सहायता में जुटे लोग। वीडियोग्रैब/एएफपी

तेजी से इधर-उधर जाते देखा गया। अस्पतालों में पहुंचे लोगों के शरीर के कई हिस्सों से खून बह रहे थे।

लेबनानी स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा संचालित क्राइसिस आपरेशंस सेंटर ने तुरंत सभी चिकित्सा कर्मियों को पेजर का उपयोग नहीं करने का निर्देश जारी किया। साथ ही घायलों के इलाज के लिए तुरंत संबंधित अस्पताल पहुंचने के आदेश दिए। वहीं, रायटर द्वारा संपर्क किए जाने पर इजरायली सेना ने इस मामले में कोई टिप्पणी करने से इन्कार कर दिया।

कई देशों में चल रहे पेजर : 1990 के दशक में मोबाइल आने से पहले कम्यूनिकेशन के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले पेजर का लेबनान ही नहीं, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, कनाडा समेत कई देशों में प्रयोग होता है। भारत में पिछली सदी के अंतिम दशक यह सेवा कुछ महीने चलकर बंद हो गई थी। इसलिए इसके बारे में लोग अधिक जानकारी नहीं रखते।

‘बुलडोजर न्याय’ पर एक अक्टूबर तक सुप्रीम कोर्ट की रोक

निर्देश

कहा, कोर्ट की इजाजत के बिना फिलहाल संपत्तियों की तोड़फोड़ या ध्वस्तीकरण नहीं हो सकता, सड़क, फुटपाथ आदि जैसी सार्वजनिक संपत्तियों से अतिक्रमण हटाने पर लागू नहीं होगा यह आदेश

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

‘बुलडोजर न्याय’ पर सुप्रीम रोक लग गई है। मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर के पहियों पर ब्रेक लगाने वाला अंतरिम आदेश दिया। गैरकानूनी ध्वस्तीकरण पर चिंता जताते हुए कोर्ट ने इसे संवैधानिक मूल्यों के विरुद्ध बताया। कहा, अगर अवैध ध्वस्तीकरण का एक भी मामला है तो वह संवैधानिक मूल्यों के विरुद्ध है। कोर्ट ने देशभर के प्राधिकारियों को आदेश दिया कि एक अक्टूबर तक कोर्ट की इजाजत के बगैर कोई संपत्ति नहीं ढहाई जाएगी, जिसमें किसी अपराध में आरोपित की संपत्ति भी शामिल है। मामले में एक अक्टूबर को फिर सुनवाई होगी।

यह आदेश जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस केवी विश्वनाथन की पीठ ने अपराध के आरोपितों की संपत्ति पर बुलडोजर चलाने का आरोप लगाने वाली याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान दिए। हालांकि उत्तर

अवैध ध्वस्तीकरण का एक भी मामला है तो वह संवैधानिक मूल्यों के विरुद्ध

प्रदेश और मध्य प्रदेश सरकार की ओर से पेश सालिसिटर जनरल तुषार मेहता ने इस तरह के अंतरिम आदेश का जोरदार विरोध किया। उनका कहना था कि कोर्ट के सामने यह धारणा पेश की जा रही है कि किसी अपराध में आरोपित समुदाय विशेष के लोगों की संपत्तियां ही ढहाई जा रही हैं, जबकि वह उदाहरण दे सकते हैं कि मध्य प्रदेश में हिंदुओं के घर भी ढहाए गए हैं। उन्होंने कहा कि याचिकाकर्ता ऐसा एक भी उदाहरण पेश करें जिसमें कानून का पालन नहीं किया गया है।

मेहता ने कहा कि किसी भी प्रभावित व्यक्ति ने याचिका दाखिल नहीं की है। हालांकि कोर्ट ने उनके विरोध को दरकिनार कर दिया और कहा कि एक सप्ताह तोड़फोड़ नहीं होगी तो क्या हो जाएगा। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि सार्वजनिक संपत्ति जैसे सड़क, फुटपाथ, रेलवे लाइनों या जल निकायों आदि का अतिक्रमण तोड़े जाने पर यह रोक लागू नहीं होगी। पीठ ने कहा कि तत्काल प्राथमिकता प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करना है ताकि न तो अधिकारी और न ही कोई व्यक्ति किसी कमी का फायदा उठा सके।

सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर का दुरुपयोग करने वालों की विध्वंसक राजनीति को किनारे लगा दिया है। बुलडोजर के पहिये खुल गए हैं और स्टीयरिंग हत्थे से उखड़ गया है। ये उनके लिए पहचान का संकट है, जिन्होंने बुलडोजर को अपना प्रतीक बना लिया था। अब न बुलडोजर चल पाएगा, न उसको चलवाने वाले। दोनों के लिए ही पार्किंग का समय आ गया है। बुलडोजरी सोच का ही ध्वस्तीकरण हो गया है। अब क्या वो बुलडोजर का भी नाम बदलकर *उसका दुरुपयोग करेंगे?*

–अखिलेश यादव, अध्यक्ष समाजवादी पार्टी

भाजपा सरकारों की अन्यायपूर्ण और अमानवीय *‘बुलडोजर नीति’* को आईना दिखाने वाला सुप्रीम कोर्ट का फैसला स्वागत योग्य है। इस तरह की बर्बर कार्रवाइयों से देश के कानून पर बुलडोजर चलाकर मानवता और न्याय को कुचलने की नीति और मंशा पूरे देश के सामने उजागर हो गई है। ‘तत्काल न्याय’ की आड़ में संविधान को उत्पीड़न और अन्याय के बुलडोजर से कुचलकर भीड़ और भय का शासन स्थापित किया जा रहा था।

–प्रियंका गांधी, महासचिव, कांग्रेस

बुलडोजर मामले में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पूरे देश में होंगे लागू पेज>>7

सिकुड़ता गरीबी का दायरा

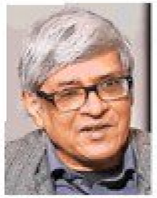

भोजन में बढ़ती विविधता, आमदनी में वृद्धि और अनाजों का घटता उपभोग आर्थिक प्रगति के सकारात्मक संकेतकों को दर्शाता है

विवेक देवराय

आदित्य सिन्हा

गरीबी के मुद्दे पर लंबे समय से गंभीर बहस होती आई है। इस बहस का एक बिंदु यह भी होता है कि आर्थिक वृद्धि का गरीबी पर क्या असर पड़ता है। अमूमन यही माना जाता है कि आर्थिक वृद्धि के विस्तार के साथ ही गरीबी का दायरा सिकुड़ता है। भारत में गरीबी का आकलन गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले लोगों की संख्या से किया जाता है। जीवन निर्वाह के लिए वस्तुओं और सेवाओं की एक न्यूनतम कसौटी को गरीबी रेखा के तौर पर मान्यता दी गई है। चूंकि घरेलू सर्वेक्षणों से प्राप्त आमदनी के आंकड़े पूरी तरह विश्वसनीय नहीं तो भारत में गरीबी रेखा को निर्धारित करने के लिए प्रति व्यक्ति मासिक खपत को पैमाना माना गया है। पिछली सदी के छठे दशक में विकसित हुई इस पद्धति को आठवें दशक में संशोधित किया गया।

गरीबी के आकलन में सटीक डाटा जितना महत्वपूर्ण है, उतना ही अहम गरीबी रेखा को भलीभांति रूप से परिभाषित करना भी है। इस कड़ी में घरेलू उपभोग व्यय सर्वेक्षण यानी एचसीईएस अहम भूमिका निभाता है। इस सर्वे में खानपान, परिधान, शिक्षा और स्वास्थ्य से जुड़ी 350 श्रेणियों पर होने वाले खर्च को शामिल किया जाता है। एचसीईएस के हालिया आंकड़ों में गरीबी के परिदृश्य की एक अलग कहानी दिखाई पड़ती है। इसके आंकड़े गरीबी की मौजूदा और संभावित दशा-दिशा को दिखाते हैं। इससे जुड़े आंकड़ों के दूसरे चरण की जमीनी पड़ताल की प्रक्रिया अभी जारी है। उनके सामने आने के बाद हमें कुछ और ठोस आधार मिलेंगे, लेकिन जो आंकड़े सामने आए हैं, उनके व्यापक विश्लेषण से देश में उपभोग के रुझान को लेकर व्यापक परिवर्तन देखने को मिले हैं। इससे स्पष्ट है कि लोग अब केवल अनाज पर ही केंद्रित न होकर अपने भोजन में दूध, मांस, फल और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों को भी तरजीह दे रहे हैं। खानपान के रुझान में इस परिवर्तन का कृषि नीति, पोषण, स्वास्थ्य और जनकल्याण जैसे पहलुओं से गहरा सरोकार है। इस रुझान के प्रमुख निष्कर्षों की पड़ताल करें तो प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय में भारी बढ़ोतरी हुई है। ग्रामीण उपभोग में 164 प्रतिशत तो शहरी उपभोग में 146 प्रतिशत की बढ़ोतरी देखी गई। इसमें बंगाल और तमिलनाडु जैसे राज्यों ने जबरदस्त तेजी दिखाई। ग्रामीण सिक्किम 394 प्रतिशत की बढ़ोतरी के साथ शीर्ष पर काबिज रहा। इसका दूसरा पहलू तो और भी महत्वपूर्ण है और वह यह कि स्वतंत्रता के बाद पहली बार ऐसा देखने को मिला है कि भोजन सामग्री पर घरेलू खर्च का हिस्सा 50 प्रतिशत से भी कम हो गया है। भोजन पर होने वाले खर्च में कमी जीवन स्तर में सुधार के साथ ही एंगेल के नियम के अनुरूप भी है कि आय बढ़ने के साथ ही भोजन पर होने वाले खर्च का अनुपात घटता जाता है। तीसरा पहलू, अनाज की खपत में गिरावट को दर्शाता है। विशेष रूप से आर्थिक तलहटी पर मौजूद 20 प्रतिशत लोगों के स्तर पर यह देखने को मिला है। इसमें प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना जैसी खाद्य सुरक्षा पहल की भी भूमिका हो सकती है, जिससे करोड़ो लोगों को मुफ्त अनाज मिल रहा है। इसके चलते लोग अपने भोजन में फल, सब्जियां, डेरी उत्पाद और एनिमल प्रोटीन शामिल कर रहे हैं। यह परिवर्तन भारत की कृषि एवं पोषण नीतियों के पुनर्मूल्यांकन की मांग करता है, जो नीतियां अनाज उत्पादन की ओर उन्मुख रही हैं। यह रिपोर्ट बताती है कि हमारी कृषि नीतियों की दिशा फसल विविधीकरण को प्रोत्साहन देने पर केंद्रित होनी चाहिए।

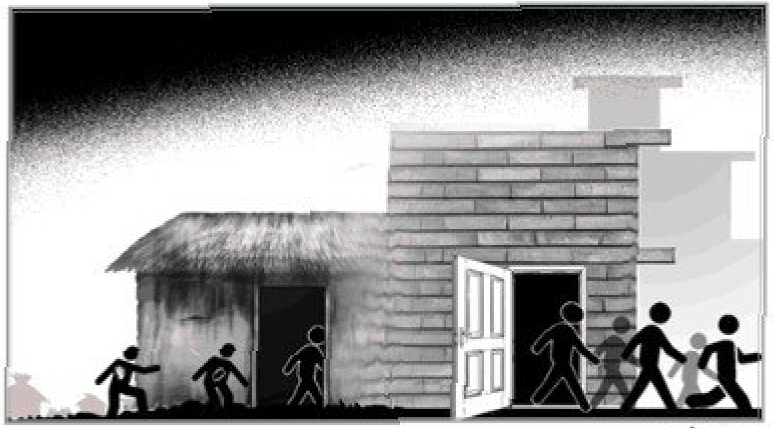

अवधेश राजपूत

मौजूदा व्यवस्था में गेहूं और धान जैसी फसलों के लिए कायम न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी और खरीदारी से जुड़ा तंत्र इनकी मांग घटने के बावजूद उनके उत्पादकों को असंगत रूप से लाभ पहुंचाने वाला है। ऐसे में बागवानी, डेरी और मवेशियों पर जोर देना टिकाऊ एवं सतत विकास की ओर अग्रसर करने के साथ ही कृषि उत्पादकता एवं पोषण के मोर्चे को भी मजबूत करेगा। यह रिपोर्ट कुछ चिंताजनक पहलुओं की ओर संकेत करती है। ऐसा ही एक पहलू प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों के बेतहाशा बढ़ते उपभोग का है। खासतौर से शीर्ष 20 प्रतिशत अमीर आबादी में यह खपत खासी बढ़ी है, जिससे जनस्वास्थ्य के समक्ष एक संकट आकार ले रहा है। तमाम शोध-अनुसंधान निरंतर रूप से यह दर्शाते हैं कि अल्ट्रा-प्रोसेस्ड खाद्य उत्पादों और मोटापा, मधुमेह एवं हृदय संबंधी बीमारियों जैसे गैर-संचारी रोगों के बीच सीधा संबंध है। ऐसे में, सरकार को इन प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों को लेकर पोषण से जुड़े पहलुओं के विनियमन का कोई उपाय करना चाहिए। साथ ही, इन खाद्य सामग्रियों के अतिशय उपभोग को लेकर जनजागरूकता का प्रसार भी उतना ही आवश्यक है। विशेष रूप से शहरी इलाकों में ऐसा किया जाना जरूरी है। रिपोर्ट कुछ और महत्वपूर्ण मुद्दों की ओर भी संकेत करती है। जैसे एनीमिया के बढ़ते मामले। इस लिहाज से महिलाओं और बच्चों की संवेदनशीलता उजागर होती है। सरकार द्वारा आयरन युक्त खाद्य उत्पादों को प्रोत्साहन देने के बावजूद एनीमिया की समस्या बनी हुई है। ऐसे में केवल आयरन युक्त खाद्य सामग्री ही नहीं, बल्कि खानपान में विविधता भी एनीमिया की चुनौती से निपटने में उतनी ही महत्वपूर्ण है। ऐसे में उन नीतियों को अपनाने की आवश्यकता महसूस होती है, जो विविधतापूर्ण, पोषण से परिपूर्ण भोजन तक पहुंच को सुगम बना सकें। विशेष रूप से गरीब परिवारों के लिए ऐसी कोई पहल और भी आवश्यक है। उपभोग का यह बदला हुआ रुझान उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में समयानुकूल परिवर्तन की आवश्यकता को भी रेखांकित करता है।

यदि उपभोक्ता के व्यवहार में परिवर्तन आ रहा है तो मुद्रास्फीति के आकलन की प्रक्रिया भी उसी अनुसार संशोधित की जाए। तभी महंगाई की सही तस्वीर सामने आ पाएगी। कुल मिलाकर, भोजन में आ रही विविधता, बढ़ती आमदनी और अनाजों का घटता उपभोग आर्थिक प्रगति के सकारात्मक संकेतकों को दर्शाता है। हमें अपनी नीतियों को भी बदलते समय के अनुसार बदलना चाहिए, क्योंकि भारत जिस प्रकार प्रगति के पथ पर अग्रसर है तो हमें स्वास्थ्य, खाद्य सुरक्षा और जनकल्याण के मोर्चे पर चुनौतियों का भी तोड़ निकालना होगा।

(देवराय प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के प्रमुख और सिन्हा परिषद में ओएसडी-अनुसंधान हैं)

response@jagran.com

Atishi named as Delhi's next CM after Kejriwal steps down

Alok KN Mishra

letters@hindustantimes.com

NEW DELHI: Aam Aadmi Party (AAP) chief Arvind Kejriwal on Tuesday resigned as Delhi's chief minister and handed the baton over to Atishi, who staked claim to form the next government, marking the latest churn in the Capital's political upheaval with just months to go for assembly elections.

Atishi, a sitting minister in Delhi whose steep rise in the party coincided with its most turbulent phase as senior leaders were jailed on corruption charges, met lieutenant governor (LG) VK Saxena on Tuesday evening, accompanied by Kejriwal and other ministers.

"The people of Delhi, the MLAs of the AAP, and I, being the chief minister (designate), will now work with only one objective till the elections in the next few months take place that we have to make Arvind Kejriwal the chief minister of Delhi again," Atishi said.

"Delhi has only one chief minister — and his name is Arvind Kejriwal."

Atishi's elevation caps a dramatic sequence of events that began on Sunday when Kejriwal

continued on →14

Outgoing Delhi CM Arvind Kejriwal with CM-designate Atishi at the LG secretariat on Tuesday. ANI

Newly anointed, Atishi says her goal is to ensure Kejriwal returns as CM

NEW DELHI: Nominated by the Aam Aadmi Party (AAP) legislative party as Delhi's next chief minister, Atishi on Tuesday said her only objective as the Capital's top elected officer is to make Arvind Kejriwal chief minister once again and to keep the government's welfare schemes running.

"The people of Delhi, the AAP MLAs and I, being the chief minister, will now work with only one objective till the elections take place in a few months — we have to make Arvind Kejriwal the chief minister of Delhi again," she said.

"Delhi has only one chief minister, and his name is Arvind Kejriwal," she said, adding that the AAP chief will become chief minister again only after the city votes his government to power during the next assembly elections, proving that they "trust his innocence". →P3

AAP VOLUNTEER TO CM: 43-YEAR-OLD'S METEORIC SUCCESS

Alok KN Mishra and Paras Singh

letters@hindustantimes.com

NEW DELHI: Atishi's ascension as Delhi's chief minister-designate marks a meteoric rise to the zenith of the national capital's political arena for a 43-year-old, who 11 years ago surrendered a career in academia to join a fledgling outfit that aimed to unsettle the city's electoral space. →P4

'MALIWAL SHOULD QUIT': AAP AFTER SHE SLAMS ATISHI

NEW DELHI: Aam Aadmi Party (AAP) Rajya Sabha MP Swati Maliwal on Tuesday described the party's decision to name Atishi as the Delhi CM designate "a very sad day for Delhi". AAP MLA Dilip Pandey hit back at Maliwal, saying "she was reading out of the BJP script". He said Maliwal should quit as MP. →P3

The Trump puzzle in US presidential polls

How Americans respond to Trump's politics, personality, policies, and the chaos that accompanies all of it, remains 2024's big riddle

Donald Trump is resilient and popular. His popularity also has severe limits. Donald Trump's politics is based on racist and anti-immigrant rhetoric. And he has a clear but narrow definition of America's economic and military interests. Take each of those four elements to understand events of the past week when Trump lost in a debate, survived a second assassination bid, attacked minorities, and projected himself as the candidate of peace even as a Republican elder shifted to the Democrats.

First, his resilience. There is the obvious physical courage it takes to come close to death twice in as many months and still be strong in the public sphere. But there is also the political resilience. Since he rode down the elevator in the Trump Tower in 2015 to announce his candidacy, political rivals and America's pundits have written Trump's political obituary at least eight times.

No one thought Trump would win the Republican nomination in 2016. No one thought he could defeat Hillary Clinton in the presidential race. No one thought he would survive the investigation around Russia's backing for his candidacy. Few believed that he could withstand the impeachment linked to his conversation with the Ukrainian president urging him to investigate Joe Biden. Few believed Americans would forgive his unscientific mismanagement of the pandemic.

No one thought that he would remain a dominant player after he refused to accept the legitimacy of the 2020 election results and even sent a mob to the United States (US) Capitol, a failed bid that resulted in a second impeachment. Everyone wrote him off after the Republicans lost the Senate and barely won the House in the 2022 midterms. And no one believed he would survive a criminal conviction and the cases. Trump defied critics each time. Today, he is more popular than ever and controls the Republican Party. That's why the Democrats remain cautious about November.

Prashant Jha

Two, Trump's popularity has severe limits. After his day of triumph in November 2016, he has lost almost every single election where either he was on the ballot or where he led the Republican Party, his loyalists dominated the list of candidates, or where issues he has championed were being tested.

This includes the 2020 presidential election which Trump lost. It includes the 2018 midterms where Republicans lost the House under a Trump presidency. It includes the Georgia Senate run-off race in January 2021 where the Democrats won the seat and flipped the Senate. It includes the 2022 midterms where far-Right Trumpist candidates were defeated in Senate races from Pennsylvania to Arizona. It includes all the referendums on abortion in states that have put the issue on the ballot. Trump may have become more popular. But under him, the Republican Party has consistently lost and its appeal to the wider electorate has diminished.

Three, racism is embedded in the Trump campaign. After spending time at the Republican National Convention, going by the sheer composition of the base and representation in leadership ranks, it was clear that Make America Great Again was essentially Make America White Again. Trump's politics around illegal immigration appeals to a reasonable impulse, the sovereign desire for safe borders. But his rhetoric is meant to stoke prejudice, hatred and fear.

In the past week, Trump and JD Vance have hurled baseless claims that illegal Haitian immigrants in an Ohio town were eating pets; neither are the town's immigrants illegal nor are they eating pets. Trump's avid supporter, the far-Right social media influencer Laura Loomer, who accompanied Trump on the plane to the debate and a 9/11 memorial, launched a racist attack on Kamala Harris' Indian roots. And Trump himself has used racist tropes against Harris. All of this is not a bug but a feature of the Trumpist White Christian project. Parts of India's Right that celebrate Trump should keep this in mind.

Donald Trump is popular, but not dominant, and triggers robust opposition. This is why it is difficult to predict the election with certainty REUTERS

Four, Trump speaks to an America that has a much narrower conception of its interests than both the Democrats and older Republicans did. This is not necessarily isolationism, for even Trump's world understands deep global interconnections. Indeed, in his first term, Trump brokered the Abraham Accords, boosted America's posture against China, sanctioned operations against Iran, engaged with North Korea, all of which indicates he will remain globally engaged.

What Trump detests are American financial and military obligations that come with being the dominant player in the international system. He doesn't quite see the benefits that come with it or pretends these benefits don't exist. He has instead framed globalisation and America's global role as bleeding American jobs, deepening inequities, and helping a military-industrial complex. This is more in tune with the everyday sentiments of Americans, burnt by Afghanistan and Iraq and frustrated by the chaos in Ukraine and Israel. Indeed, Dick Cheney's endorsement of Harris proves to Trump's base that he has cleansed the party of people who were responsible for bad wars, of which Iraq is the most obvious example. This projection as the candidate of peace committed to basic US interests and focused on its economic well-being is a major source of Trump's appeal. But this vision also upsets older assumptions and is contested by those who want a more internationalist role, as the assassination bid by an avid Ukraine sympathiser over the weekend showed.

Trump is popular but not dominant and triggers robust opposition. This explains why it is difficult to predict the election with certainty. Trump borrows identity-based chauvinism from the Right and criticism of liberal economics and foreign policy from the old Left. This explains why Trump is hard to box into an ideological category. Whether enough Americans like his personality, policy mix and the chaos that comes with it remains the central question of 2024.

The views expressed are personal

The continuing distribution of the death penalty

Shailesh Kumar

Lecturer in Criminal Law at Royal Holloway, University of London, a Commonwealth Scholar, and an Editorial Board member of the Project39A Criminal Law Blog

The life of the death sentence in India has been unending, and like a phoenix revives itself in different forms every now and then. The latest addition to this is the Aparajita Woman and Child (West Bengal Criminal Laws Amendment) Bill, 2024, adopted by the West Bengal government, the reason being the brutal rape and murder of a doctor at Kolkata's R.G. Kar Medical College and Hospital. It seeks to amend the Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023 (BNS), the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023 and the Protection of Children from Sexual Offences Act, 2012, in their application to the State of West Bengal. Among other things, it introduces the death penalty for the offence of rape.

While it has been unanimously passed by the Bengal Assembly, the State Governor was critical but has referred it to the President of India Droupadi Murmu for consideration. In the same month of August, there were several such cases in other States with the survivors being Dalit/Adivasi women and children. In 2022 alone, the National Crime Records Bureau recorded 31,516 rapes in India, nearly four each hour, and 248 cases of murder with rape/gang rape. Rajasthan, Uttar Pradesh, and Madhya Pradesh topped the list with 5,399, 3,690, and 3,029 recorded cases of rape, respectively.

Global data

In global figures from Amnesty International, at the end of 2023, nearly three quarters of countries had abolished the death penalty in law or practice: 112 countries had completely abolished the death penalty in law for all crimes, while 144 countries overall had abolished the death penalty in law or practice. But 55 countries still retained the death penalty in law and practice. In South Asia, while Bhutan and Nepal are the only abolitionists for all crimes, the Maldives and Sri Lanka are abolitionists in practice. India, along with Afghanistan, Bangladesh, Pakistan, are the retentionists. Project39A reports that in 2023 alone, India had 120 recorded death sentences. There were no recorded executions, and the number is down from 167 in 2022. Moreover, there were 561 people under the death sentence in India at the end of 2023, a constant rise since 2019, when it was 378. It is also the highest death row population in a calendar year in around two decades.

Most of such death row prisoners spend several years on death row, with some being exonerated later. They have severe physical, psychological and mental health problems and without any state compensation, which suggest grave procedural flaws and perhaps caste, class, and religious biases that pervade different institutions of the Indian criminal justice system and the people who exude power through them. Some of these prisoners commit suicide, signifying the inhuman prison conditions in which they are made to live, including prison overcrowding, as undertrials are mostly from the marginalises communities and left to fend for themselves. They continue to constitute three-fourths of the total number of incarcerated people in India.

Creating a safer environment for women and children is a complex issue; punishment alone cannot change society

On VAWC and societal responses

Unfortunately, the use of 'decolonisation language' that gave birth to the BNS (replacing the Indian Penal Code), while enabling a few positive changes, has increased the number of offences punishable by death from 12 to 18. India has shifted to a more deterrent regime for sexual offences without any significant change in women's safety and empowerment. A glance at the nature of offences where the death sentence has been given by sessions courts in 2023, shows murder involving sexual offences at the top of the chart (64). Sexual violence against women and children (VAWC), particularly where the victim is killed, most often led to outbursts of public anger, grief, and shock, followed by the demand of capital punishment from certain sections for the rapists, who are often termed as *rakshas, haivaan, wehshi darinda*.

This framing creates an 'othering' – as if the accused is not from the same society that we inhabit – and justifies death for them as a tool for avengement, which also seems to be rooted in India's religious and societal culture that celebrates death (the killing of devils by gods and goddesses). Such calls for 'justice' to victims mostly use the honour of the family, community, and nation, ignoring the victim's autonomy and what they want, which is also reflected in judicial discourse. On the other hand, there is a normalisation and politico-legal tolerance of everyday VAWC by men, including their public flogging, sexual violence, and killing – outside by strangers without any public intervention, and at home by husbands and relatives. Worryingly, searches for victims' videos trend on Google and explicit sites.

The recommendations made by the Justice Verma Committee argued that the death sentence does not necessarily act as a deterrent against crimes such as sexual offences, including gang rapes. However, the Union Cabinet did not consider those recommendations. So, if the objective behind the death penalty is not fulfilled, the carceral politics of sexual violence must be dismantled by infusing abolitionist feminism. A key concern is also to bring human rights-based language to masses, the majority of whom do not have access to it, and whose thoughts towards the death penalty are shaped by cultural and religious narratives. There must be an abolitionist feminist movement to refuse the death sentence and even life imprisonment without parole as responses to sexual violence including rape. This movement should seek to understand and work upon the social causes and cultural conditions that lead to VAWC.

It also needs to work on the structural issues of redistribution of land and wealth for the marginalised communities, their representation in all spaces and institutions – both private and public – and a radical shift towards properly funded public education and health care. Governments and society need to work on the kind of targeted support and a range of state facilities rape survivors need in order to access education, employment, health, marital and family life. They also need to provide support to families of rape survivors, particularly minor siblings, if any, in terms of their access to education and resources, and take part in community building and a realisation of fraternity to ensure their dignity that the Indian Constitution upholds.

Complex issues but there must be a start

There need to be victim-centred procedural and institutional reforms and some sort of '*beta padhao, beti bachao* (educate the son, to protect the daughter') policy initiative to eliminate the patriarchal notion of the honour of the family, community, and nation residing in female bodies and virginity. Invisibilising and ignoring the problems mentioned above will make the abolition movement appear superficial to say the least and forced from the top. The death penalty is the safest escape route from accountability as it does not burden the state with the hard work of reforming the police, prosecution, judiciary and supporting survivors. A culture of utilising existing research for an evidence-based informed policymaking by the central and State legislatures needs to be inculcated to avoid knee-jerk populist reactions that lead to criminal injustice. Additionally, research needs to be conducted on if and how the socio-religious background of judges plays a role in them awarding the death sentence.

Indian society is again striving for social change through legal reform. It seeks the care, the safety and the support for rape survivors and their families, alongside state accountability. But we must remain attentive to how the apparatus of laws (including contract, family, labour and property laws) constructs the socio-economic status of women and children, particularly from the oppressed castes and other marginalised communities. It asymmetrically distributes wealth, knowledge and power.

Abolition of the death penalty and creating a safer environment for women and children are complex issues. They require understanding, teaching, and engaging the law, critically. There must be an admission of and public talk about caste, race, religion and gender-based violence through an intersectionality lens, including by the organisations and the people who champion these causes. Feminists argue that sexual offences are more about power than sex.

There is a need for public and judicial awareness campaigns debunking the myth of the death sentence leading to a reduction in VAWC and to bring gender equity from within the private sphere (family) to the public sphere, rather than distributing death penalty and sentence inflation. Punishment alone cannot change society.